बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 292

चीन की मंदी

चीन में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2018 में घटकर 6.6 फीसदी पर आ गई। यह दर सन 1990 से अब तक की सबसे धीमी जीडीपी वृद्धि दर है। चीन के लिए यह बात काफी मायने रखती है। चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर सालाना आधार पर 6.4 फीसदी रही। इससे यह संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है। जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों में सुधार भी सन 2017 की वृद्धि को संशोधित करके कम करने के बाद आया है। इसका अर्थ यह भी है कि आधार प्रभाव सकारात्मक रहा है। चाहे जो भी हो चीन की वृद्धि के आंकड़ों पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में यह अपेक्षाकृत कमजोर आंकड़ा शीर्षक में जाहिर आंकड़ों से परे कहीं बड़ी कमियों को अपने पीछे छिपाए हुए हो सकता है।

चीन की मंदी की प्रकृति चक्रीय नहीं बल्कि ढांचागत है। तीन दशक की जोरदार वृद्धि के दौरान चीन एक विशिष्ट निवेश और निर्यात आधारित मॉडल के सहारे आगे बढ़ रहा था। वित्तीय बचत और विदेशी निवेश का प्रयोग बड़ी पूंजी खपाऊ परियोजनाओं तथा निर्यातोन्मुखी विनिर्माण में किया गया। इससे रोजगार और आय में इजाफा हुआ और चीन दुनिया की फैक्टरी के रूप में सामने आया। उसका व्यापार अधिशेष दुनिया के अधिकांश देशों से अधिक था। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सरकार ने इस मॉडल पर और जोरशोर से काम करने की बात सोची। ऐसे में विभिन्न पूंजी आधारित क्षेत्रों को जमकर सस्ता ऋण मुहैया कराया गया। इस दौरान वृद्धि तो मजबूत बनी रही लेकिन पूंजी की उत्पादकता में काफी कमी आई। बीते वर्ष तीन चौथाई वृद्धि खपत से आई। इससे यह संकेत मिला कि अब खपत आधारित क्षेत्र अब विकास के वाहक बन चुके हैं।

चीन इस ढांचागत समस्या से भलीभांति अवगत है और यही कारण है कि वहां काफी समय से चीन की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से संतुलित करने की बात चल रही है। इस संतुलन को निर्यात से हटाकर नवाचार और खपत में निवेश बढ़ाकर हासिल किया जाना है। इसके पीछे एक ठोस दलील है: उच्च मध्य आय से उच्च आय के दायरे में जाने और मध्यम आय के जाल से बचने के लिए चीन को उत्पादकता बढ़ानी होगी जो मूल्यवर्धन शृंखला में ऊपर जाने और अपनी तमाम प्रक्रियाओं में नवाचार बढ़ाने से आएगी। पुनर्संतुलन की यह प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर बदलाव के दौर में वृद्धि को धीमा करेगी। बहरहाल, बदलाव का क्रियान्वयन उम्मीद से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ है। मिसाल के तौर पर राजनीतिक चिंताओं ने हस्तक्षेप किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह बात राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है कि वह वृद्धि दर ऊंची बनी रहे और आय बढ़ती रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के लोगों के साथ पार्टी के जुड़ाव पर असर पड़ेगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था के अनुत्पादक क्षेत्रों में ऋण की आवक को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा निजी क्षेत्र जिसकी इस पुनर्संतुलन में अहम भूमिका हो सकती थी, वह पार्टी की मौजूदा नीति से विरोधाभासी है। चीन ने शोध आदि को लेकर संसाधन झोंके हैं और इनका कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। परंतु इन शोध के उत्पाद को अंतिम उत्पाद में बदलना काफी कठिन रहा है।

चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की बात की है जिस पर नजर रखनी होगी। अमेरिका के साथ कारोबारी तनाव कुछ मायनों में निर्यात की महत्ता कम करने में सहायक हो सकता है। भारत के लिए प्रश्न यह है कि यह ढांचागत मंदी वृद्धि को किस हद तक प्रभावित करेगी। एक ओर जहां इसमें भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति शृंखला में जगह बनाने का अवसर बना है, वहीं यह भी सच है कि बिना अहम घरेलू सुधारों के वह सपना भी अधूरा रह जाएगा।

अजय मोहंती

विकास नीति और बजट के बीच का सामंजस्य

राजकोषीय नीति निर्माण में राजकोषीय विवेक, अनुपालन और उसे सहज बनाना चाहे जितना वांछित हो लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नितिन देसाई

एक फरवरी, 2019 को वित्त मंत्री इस सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे जो संभवत: अंतरिम बजट होगा क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। नियमित बजट आम चुनाव के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। अरुण जेटली इस अवसर का इस्तेमाल बीते पांच वर्ष में अपनी सरकार के राजकोषीय नीति प्रबंधन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने में करेंगे। हाल की घोषणाओं में जहां चुनाव पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के रास्ते से विचलन नजर आया है, वहीं वह इस मौके का इस्तेमाल कुछ व्यय प्रस्तावों और चुनावी जीत दिलाने वाली नीतियों की घोषणा करने में भी किया जाएगा।

राजकोषीय नीति का रिपोर्ट कार्ड मध्यावधि की राजकोषीय नीति को लेकर जारी किए गए दो नीतिगत वक्तव्यों में उल्लिखित वक्तव्यों पर केंद्रित होगा। उक्त नीति बजट का एक हिस्सा तैयार करता है। बीते कुछ वर्षों के दौरान इन वक्तव्यों की भाषा पर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजकोषीय नीति का प्राथमिक लक्ष्य जीडीपी की तुलना में राजकोषीय घाटे में कमी करना, कर/जीडीपी अनुपात में सुधार करना, कर ढांचे को सहज बनाना और अनुपालन बेहतर करना है। इस वर्ष के बजट में आंकड़ों का इस्तेमाल यह जताने के लिए किया जाएगा कि वित्त मंत्री के पिछले बजट इन लक्ष्यों को हासिल करने में किस हद तक कामयाब रहे। परंतु यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये लक्ष्य पर्याप्त हैं?

कर/जीडीपी अनुपात व्यापक विकास नीति का अहम घटक है। परंतु इस अनुपात के बढ़ने की गति को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे पर होने वाला व्यय बढ़ेगा क्योंकि आर्थिक औद्योगीकरण और शहरीकरण तथा बढ़ती समृद्धि लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ा रहे हैं। सार्वजनिक व्यय के वांछित स्तर का मध्यम से दीर्घकालिक आकलन हमारी सार्वजनिक राजकोषीय नीति का अंग होना चाहिए। इस व्यय का दायित्व केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन पर होता है।

सार्वजनिक व्यय की दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो भी अल्पावधि की राजकोषीय अनिवार्यताओं का सकारात्मक प्रयोग संभव है। वृहद आर्थिक कारणों से जरूरी राजकोषीय प्रोत्साहन दीर्घावधि की विकास नीति के लिए मददगार हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2008 के वैश्विक संकट के बाद जब राजकोषीय प्रोत्साहन की आवश्यकता थी तब चीन ने व्यय में जीडीपी के 3 फीसदी के बराबर और दक्षिण कोरिया ने 5 फीसदी इजाफा किया ताकि कृत्रिम मेधा, स्मार्ट फोन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार और विंड टर्बाइन जैसे उद्योगों के शोध और विकास पर खर्च किया जा सके। इनकी बदौलत अब वे तकनीकी जगत में पश्चिम के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। वहीं हमने 2008 के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रयोग कल्याण योजनाओं में इजाफा करने में किया।

विकास नीति आय की असमानता कम करने का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति, प्रत्यक्ष कर दर ढांचे और बजट में सब्सिडी आदि के जरिये आय के वितरण को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष कर मामले में घोषित नीति कर दायरे को व्यापक बनाने और कर दर को हल्का बनाए रखते हुए रियायतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की है। आयकर की 10-20-30 प्रतिशत की दर का ढांचा दो दशक से चल रहा है और उसने उदारीकरण के पहले के अपेक्षाकृत प्रगतिशील कर ढांचे को प्रतिस्थापित किया है। इस अवधि में गैर कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्तिगत आयकर संग्रह 2003-04 के 2 फीसदी से बढ़कर 2013-14 में 3 फीसदी और 2013-14 में 3.5 फीसदी हो गया।

नोटबंदी के कारण अनुपालन में किसी बड़े सुधार का संकेत नहीं निकलता है। अगर तमाम आय कर संग्रह गरीबों को हस्तांतरित करने के लिए उपलब्ध हो तब भी आय के पुनर्वितरण का असर सीमित होगा। करदाताओं को दी जाने वाली रियायत, लाभांश और पूंजीगत लाभ के साथ बरती जाने वाली उदारता और विरासती कर की अनुपस्थिति बताती है कि न तो यह और न ही इससे पिछले प्रशासन ने कर व्यवस्था का प्रयोग पुनर्वितरण के लिए किया। इसके लिए केवल मूल्य सब्सिडी और कल्याण योजनाओं का इस्तेमाल किया गया।

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के सुदीप्त मंडल और शताद्रु सरकार ने अनुमान लगाया है कि 2015-16 में जीडीपी के 6 फीसदी के बराबर सब्सिडी और जीडीपी के 4 से 5 फीसदी के बराबर कर रियायत ऐसी रहीं जिनका औचित्य साबित करना मुश्किल है। खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और सफाई पर दी जाने वाली सब्सिडी जीडीपी के 2 फीसदी के बराबर रही। अब उत्पाद और सेवा विशेष की सब्सिडी के स्थान पर प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण की बात सुनने को मिल रही है और हमें इस बजट में इस दिशा में शुरुआत देखने को मिल सकती है। परंतु इससे आय के वितरण में तब तक कोई अंतर नहीं आएगा जब तक कि अवांछित सब्सिडी और प्रत्यक्ष कर रियायत में नाटकीय अंदाज में कमी नहीं आती और आय का पूरकीकरण जीडीपी के 2 फीसदी के ऊपर नहीं जाता। करों और सब्सिडी के सामाजिक और निजी लाभ और लागत को अलग-अलग करके देखना भी आवश्यक है। इसका एक उदाहरण संचारी रोगों का नि:शुल्क टीकाकरण भी है जिसे उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि संक्रमण से होने वाले लाभ भविष्य में सामने आते हैं। 400 रुपये प्रति टन का कोयला उपकर भी इसका उदाहरण है जिसे कार्बन उत्सर्जन की सामाजिक लागत के रूप में उचित ठहराया जा सकता है।

नकारात्मक बाह्यता निर्मित करने वाले कर और सब्सिडी प्रतिस्पर्धी उत्पादों के कराधान में अंतर पैदा करते हैं। एकल जीएसटी के प्रति प्रतिबद्धता के सामने ये नहीं ठहरेंगे। ऐसे में निजी और सामाजिक लागत और लाभ के अंतर के व्यवस्थित आकलन पर आधारित उपकर और सब्सिडी से बात बन सकती है।

राजकोषीय विवेक, अनुपालन और सामान्यीकरण वांछित हैं लेकिन नीतिगत डिजाइन के केंद्र में नहीं हैं। राजकोषीय नीति और विकास की नीति के बीच का संबंध इस सिलसिले में खो सा गया है। हमें आय के वितरण, खपत और उत्पादन चयन पर राजकोषीय नीति के असर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वे कारक हैं जो पर्यावरण, संसाधनों के प्रयोग के स्थायित्व और स्वास्थ्य आदि कारकों को प्रभावित करते हैं।

कोटलर के मानदंडों पर खरा नहीं उतर पाएंगे भारतीय नेता

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

प्रबंधन गुरुओं के बीच जो स्थान पीटर ड्रकर का था, वही स्थान मार्केटिंग पेशेवरों के बीच फिलिप कोटलर का है। इसी वजह से अपने नाम पर एक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को देने के कोटलर के फैसले को अजीब कहा जा सकता है। इतना अजीब कि इससे मीडिया हाउस इस फैसले की तह में जाने को लेकर प्रोत्साहित हुए। द वायर ने पूरी सतर्कता से शोध कर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें इस पुरस्कार का संबंध सऊदी सरकार के स्वामित्व वाले पेट्रोरसायन समूह से जोड़ा है। इस समूह की एक इकाई गुजरात में है और यह भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। यह बात भी सामने आई है कि निर्णायक मंडल के दो सदस्य- विज्ञापन उद्योग के दिग्गज वाल्टर वियरा और गौतम महाजन ने पुरस्कार के फैसले की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।

इसके बाद इस मुद्दे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और कोटलर को मार्केटिंग जनरल के संपादक क्रिश्चियन सरकार को एक 'साक्षात्कार' के जरिये सफाई देनी पड़ी। उनका इस सवाल का जवाब जरूर कुछ अहमियत रखता है कि उनकी परिभाषा के मुताबिक राजनीतिक नेतृत्व का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। असल में तीसरे सवाल से पूरा साक्षात्कार मनोरंजक है, जिसे न कोटलर और न ही सरकार नकार सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'इस पुरस्कार के पीछे सोच एक प्रमुख जन नेता को सम्मानित करना है, जिसने उस देश में लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि को एक नया जीवन दिया है।' कोटलर नेतृत्वकर्ता पुस्कार के लिए वह नेता पात्र है, जो प्रतिनिधि सरकार और सामाजिक न्याय में भरोसा रखता है। वह यह मानता है कि एक अच्छा समाज स्वस्थ कारोबारी माहौल बनाएगा। जो उद्यमों को अपनी चर्चा के केंद्र में तीन तथ्यों- संतुलित लाभ, लोगों और ग्रह को रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो लोकहित के लिए पूरी ईमानदारी और मनोयोग से काम करता है।

इन मानदंडों पर प्रधानमंत्री सबसे आगे रहे। उन्होंने वैश्विक मंच पर देश की छवि और पहचान सुधारी है। डब्ल्यूएमएस में एक समिति ने उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर संभावित नेताओं पर मतदान किया था। उन्होंने न अन्य नेता चिह्नित किए और न ही उनसे प्रतिस्पर्धा में शामिल अन्य नेताओं के नाम बताने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, 'अंतिम फैसला मेरा था।' ये सब बातें सीधे मोदी के लिए हैं, जो कॉरपोरेट शब्दावली (जैसे देश का नेता राष्ट्र के ब्रांड का संरक्षक) में आनंदित होते हैं और चंद्रबाबू नायडू की तरह खुद को सीईओ के प्रकार का राजनेता मानना पसंद करते हैं। इस अवधारणा के जोखिम डॉनल्ड ट्रंप में देखे जा सकते हैं। ट्रंप दावा करते हैं कि उनका कारोबारी कौशल उन्हें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है।

कोटलर के चार मापदंडों को सरसरी पढ़ने से न केवल इस मार्केटिंग गुरु के तर्कों की कमजोरी बल्कि फैसले के कॉरपोरेट मानकों को राजनीति और राजनेताओं पर लागू करने के जोखिम का भी पता चलता है। यह जोखिम तब और बढ़ जाता है कि जब इन मानदंडों को भारत जैसी अत्यधिक जटिल और विविधतापूर्ण राजनीति पर लागू किया जाता है। कोटलर ने ऊपर जिन मानदंडों का उल्लेख किया है, उन्हें पूरा करने का दावा किसी भी लोकतंत्र का राजनेता कर सकता है। इसी तरह भारत जैसे देश में राजनीतिक पर बड़े वाद-विवाद जारी रहते हैं। ऐसे देश में इन चार मानदंडों को लेकर आसानी से सवाल उठाए जा सकते हैं। इन चार मानदंडों में चौथे पर सबसे पहले विचार करते हैं। 'ईमानदारी और मनोयोग से जनहित के लिए काम करते हैं।' ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इस तर्क को खारिज कर सकते हैं। वे इसके लिए किसानों, लघु एवं मझोले उद्योगों, नोटबंदी के दौरान नौकरी गंवाने वालों, भीड़ की हिंसा के शिकार लोगों के परिवारों, मुस्लिम समुदाय और दलितों का उदाहरण देते हैं।

दूसरे मानदंड 'यह मानते हैं कि अच्छा समाज स्वस्थ कारोबारी माहौल बनाएगा' के बारे में क्या कहेंगे? कारोबार से बहुत से लोग इस फैसले से सहमत हो सकते हैं, लेकिन नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को हड़बड़ी में लागू करने, आयात बिल बढ़ने आदि के कारण बहुत से लोग इस फैसले से सहमत नहीं होंगे।

तीसरा मानदंड है-'उद्यमों को तीन तथ्यों- संतुलित लाभ, लोगों और ग्रह को अपनी बातचीत के केंद्र में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।' लेकिन मोदी के कंपनी समूहों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने के साक्ष्य बहुत कम नजर आते हैं। असल में पूर्व सरकार ने कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च को लेकर अतार्किक फैसला देने के बावजूद इस मोर्चे पर बेहतर स्थिति में होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही वरिष्ठ प्रबंधन से अपने वेतन-भत्तों में कटौती करने का आग्रह किया था, लेकिन इस बयान को लेकर उन्हें कारोबारी समुदाय से कोई प्रशंसा नहीं मिली।

कोटलर की इस धारणा को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि मोदी ने वैश्विक मंच पर देश की छवि और पहचान सुधारी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ताजा आंकड़े विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। क्या उनका इशारा विश्व योग दिवस की तरफ है या उनकी सरकार के शुरुआती वर्षों में जुटाए गए एनआरआई प्रशंसकों की तरफ है? इसमें जॉर्ज बुश के साथ डॉ. सिंह की बहुत सतर्कता से किए गए परमाणु समझौते की अनदेखी की गई है। सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका अदा की है।

मोदी के प्रति निष्पक्ष रहें तो कोई भी अन्य भारतीय राजनेता कोटलर द्वारा सम्मान के लिए तय किए गए मानदंडों पर खरा नहीं उतर पाएगा। लेकिन ये मानदंड पहली बार लागू किए गए हैं, इसलिए आप यह जानने को उत्सुक होंगे कि दूसरा फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार कौन जीतेगा।

कानाफूसी

पारिवारिक मामला

सोशल मीडिया पर और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ नकुलनाथ की मौजूदगी ने इन अफवाहों को बल दिया है कि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ के सुपुत्र आगामी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। फिलहाल यह सीट उनके पिता के पास है लेकिन चूंकि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं इसलिए पद संभालने के छह महीने के भीतर उनका विधानसभा में पहुंचना जरूरी है। गौरतलब है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से नौ बार सांसद रह चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से नकुलनाथ छिंदवाड़ा में काफी सक्रिय हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ऋण माफी और कृषि उपकरणों की खरीद जैसी राज्य सरकार की विभिन्न पहलों पर अनुदान आदि का प्रचार प्रसार करते अक्सर

संदेश और संदेशवाहक

प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाए जाने के बाद पार्टी के नेता तो उत्साहित हैं ही, जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर भी इससे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पेशे से चुनाव रणनीतिकार रहे किशोर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अभियान का प्रबंधन किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि यह भारतीय राजनीति की सर्वाधिक प्रतीक्षित घटनाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान किशोर अक्सर प्रियंका गांधी के साथ मशविरा करते थे लेकिन चुनाव के बाद उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। बहरहाल अब अगर किशोर चाहें भी तो भी उनके लिए कांग्रेस में पुनर्वास मुश्किल होगा क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा है कि किशोर को पार्टी में नंबर दो की हैसियत देना उनका अकेले का निर्णय नहीं था बल्कि उन्हें पार्टी में पद देने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश को दो बार फोन किया।

आपका पक्ष

सरकारी नौकरियों की घोषणा

केंद्र सरकार ने संभवत: अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे में नई नौकरियों की घोषणा की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे में 2 लाख 30 हजार भर्तियां की जाएंगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गठन के बाद इन पांच वर्षों में अबतक इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों की घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने कई विभाग के रिक्त पड़े खाली पदों को समाप्त भी कर दिया था। पिछले पांच साल से बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। बहरहाल केंद्र सरकार का यह फैसला सराहनीय है। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने गरीब सवर्ण को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा भी की थी। इन घटनाओं का क्रमवार चलना राजनीतिक लाभ लेना भी हो सकता है। बहरहाल गरीब सवर्ण आरक्षण तथा रेलवे में रिक्तियां से बेरोजगार युवकों में आस बंधेगी।

किशोर कुमार, नोएडा

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में 2 लाख 30 हजार रिक्तियां निकालने की घोषणा की है

विस्थापन की समस्या

आज गांवों से शहरों की ओर रोजगार के लिए विस्थापन लगातार जारी है जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी जुटा पाना मुश्किल है। सरकार को गांवों में रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे विस्थापन की इस समस्या से बचा जा सके। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश के गांवों का विकसित होना काफी जरूरी है।

श्रीनिवास बिश्नोई, बीकानेर

क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखें

पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक भारी बहुमत से पारित कर दिया। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। प्रस्तावित आरक्षण वर्तमान में 49.5 प्रतिशत कोटे से अलग होगा। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है और आरक्षण भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर इस संविधान संशोधन विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। वास्तव में आर्थिक रूप से ही आरक्षण का वैज्ञानिक आधार हो सकता है। मेरी राय में क्रीमी लेयर को आरक्षण के इस सुविधा से बाहर रखना चाहिए ताकि आरक्षण का पूरा लाभ निचले स्तर के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल सके।

डॉ एमएस सिद्दीकी, फर्रूखाबाद

सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा मिलेगा

मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण के निर्धारित मापदंड में वार्षिक आय 8 लाख रुपये, 5 एकड़ जमीन या एक हजार फुट के मकान की सीमा तय की गई है। ये मापदंड कितने जरूरतमंदों को लाभ पहुंचा सकेगा। यह इसलिए विचारणीय है कि अगर सरकार 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को गरीब मान रही है तो फिर 3 लाख रुपये वार्षिक आय वालों से आयकर क्यों वसूल रही है। क्या 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले गरीबी की सीमा में नहीं आते। केंद्र तथा राज्य सरकारों और सभी राजनीतिक दल को यह विचार करना चाहिए कि देश में जरूरतमंद तबके को आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाए।

साधना जैन, मुंबई

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।